से राज्यों में डेरी परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में किन-किन शहरों में स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वोरचन्दभाई शाह) : (क) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है जिसका मूल उद्देश्य सिटअरलैंड सरकार के सहयोग से राज्यों में डेयरी परियोजनायें स्थापित करना हो।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

Uniform code for cooperatives

*1S9. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

■ (a) whether Government propose to have a uniform code and legal rules for the all co-operatives in the country; and

' (b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHAND-BHAI SHAH): (a) and (b) Co-opera, tive Societies" is a State Subject. The Stats Governments are responsible for the supervision of, and guidance to, the co-operative societies in the States. For this purpose, each State Government has enacted its own co-operative societies law.

The Government of India, in the Planning Commission, hav$_e$ appointed a Committee to assess the existing situation of the co-operative movement and nature of co-operative laws, so as to recommend a model for co-operative law in the country. The Committee has prepared a draft Bill, which has been circulated to the State Governments, national-level co-operative societies, agencie$_s$ interested in the promotion of co-operative activities and individual co-operators. The final draft will be prepared by the Committee in the light of these comments and the same is expected to be submitted to the Planning Commission by March, 1991.

उन्नत प्रकार के बीज

*140. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए किस-किस प्रकार के उन्नत बीच उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ख) इन बीजों को किसानों को उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों में विभिन्न फसलों की 235 किस्में अधिसूचित की गई हैं।

(ख) बीजों के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों केन्द्र शासित क्षेत्रों की है, जो यह काम विभिन्न राज्य एजेंसियों के द्वारा करते हैं। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय बीज निगम और राजकीय फार्म निगम के जरिये इस काम में उनकी सहायता करती है। फसल विकास कार्यक्रमों के तहत भी इन्हें सहायता दी जाती है।

गरीबी को कम करने के लिये प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों की निष्फलता

@993. **श्री राम जेठ मलानी** :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26

@Previously Unstarred Question No. 933 transferred from l$_s$t January, 1SS1.

नवम्बर, 1990 के फ़ाइनेन्सियल एक्सप्रेस में "फ्लाज इन प्लानिंग इम्पेड पावर्टी एलीविएशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गरीबी को कम करने के लिए प्रारंभ किये गये कार्यक्रम अकुशलता, भ्रष्टाचार आदि के कारण अपेक्षित सीमा तक सफ़ल सिद्ध नहीं हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछले दशक में ग्रामीण गरीबी को कम करने में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का सकारात्मक योगदान रहा है, यद्यपि इन कार्यक्रमों के प्रभाव तथा कार्यक्षमता में सुधार किये जाने की काफ़ी गुंजाइश है। विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकारों तथा बकों के साथ परामर्श करके इन कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिये अपेक्षित सुधारात्मक तथा समर्थनात्मक कारवाई की गई है।

मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रमों की कड़ी निगरानी करने की एक पद्धति चल रही है। इसके अलावा, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में खामियों का पता लगाने तथा राज्य सरकारों के माध्यम से उनको दूर करने के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी एजेंसियों की मार्फ़त एक नियमित समवर्ती मूल्यांकन कराया जाता है। राज्य सरकारों को कदाचारों को रोकने के लिये सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाने की सलाह दी गई है।

Number of dismissed Railway Employees during their agitations

904. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of Railway Employees dismissed from service during the last ten years in connection with various agitations by the Railway workers Zone-wise;

(b) how many of these dismissed workers are trade union activists/ office bearers;

(c) the number of Railway employees suspended during the last five years in connection with agitations zone-wise; and

(d) whether the dismissed|suspended employees are being taken back in service following decision by previous Government?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a), to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Introduction of New Trains

995. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the names of new trains introduced since 2nd October, 1990 together with their starting points and destinations;

(b) whether in view of the ever increasing traffic, any new train is proposed to connect Delhi-Shimlt; and

(c) if so, by when it is likely to be introduced?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) 240112402 Shramjeevi Express between New Delhi-Patna and 24031 2404 Shramik Express between Kan-pur-Varanasi.

(b) and (c) At present 2 pairs of trains are available between Delhi and Simla with transhipment at Kalka. However, at present there is no proposal for an additional train.